बढ़ती मंहगाई, पेट्रोल की कीमत और RBI

- मांग और आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होने पर वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति या मंहगाई के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में रुपये की क्रय शक्ति क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे पहले जितना ही समान खरीदने के लिए अधिक भुगतान करना होता है।
- मुद्रास्फीति सामान्यतः दो कारणों से होती हैं, इन्हें मांगजनित कारक और लागतजनित कारक के नाम से जाना जाता है।
- जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन स्थिर रहें या कम हो जाये लेकिन मांग में वृद्धि हो जाये तो इसे मांगजनित मुद्रास्फीति **(Demand-Pull Inflation)** कहते हैं। उत्पादन बढ़ने पर या मांग में कमी आने पर यह मंहगाई नियंत्रित हो जाती है।
- यदि उत्पादन के कारकों (भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, ऊर्जा) की लागत में वृद्धि होने से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो इसे लागतजनित मुद्रास्फीति **(Cost-Push Inflation)** कहते हैं। इस प्रकार की मुद्रास्फीति कई कारकों पर निर्भर करती है।
- मुद्रास्फीति की वजह से निश्चित आय वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें श्रमिक, अध्यापक, कंपनी के कर्मचारी, मजदूर, वह सभी वर्ग शामिल हैं, जिन्हें निश्चित आय ही प्राप्त होती है। इनकी आय तो स्थिर रहती है लेकिन मंहगाई की वजह से खर्च बढ़ जाता है,

जिसकी वजह से या तो उन्हें खर्च में कटौती करनी होती है या बचत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- मुद्रास्फीति की अवस्था में मांग में कमी आती है, जिससे उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- मुद्रास्फीति से ऋणदाता को नुकसान होता है क्योंकि मंहगाई के कारण उसके रुपये का मूल्य कम हो जायेगा। इसलिए मुद्रास्फीति की अवस्था में ऋण प्रवाह कम हो जाता है।
- निवेश में भी कमी देखी जाती है।
- मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिससे आयात सस्ता होता है, अधिक होता है और निर्यात महंगा एवं कम हो जाता है। आयात बढ़ने और निर्यात कम होने से भुगतान संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- मुद्रास्फीति के कारण सरकार के सार्वजनिक व्यय बढ़ जाते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए सरकार नये कर लगाती है या पुराने कर की दर में वृद्धि करती है, जिसका बोझ टेक्स भुगतान करने वाले वर्ग पर पड़ता है।
- मुद्रास्फीति से कुछ वर्गों को फायदा भी होता है। इसमें उत्पादक वर्ग, उद्यमी वर्ग और कृषक वर्ग शामिल हैं।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार किये जाने वाले मुद्रास्फीति को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसमें अन्य मंहगाई के

साथ खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है। जब हम मुद्रास्फीति की गणना खाद्य एवं ईंधन में होने वाले उतार-चढ़ाव के बिना करते है तो इसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं।

- अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए घातक मानी जाती है। वहीं 2-3 प्रतिशत मुद्रास्फीति बाजार में उत्साह/ऊर्जा का कार्य करती है और इसे ठीक माना जाता है।
- मंहगाई को नियंत्रित करने में **RBI** की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है, इसी कारण **RBI** मौद्रिक नीति समिति का गठन 27 जून, 2016 को किया गया था। यह आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाये रखने का कार्य करती है। यह मंहगाई दर को 4 प्रतिशत तक नियंत्रित रखने का प्रयास करती है।
- मौद्रिकनीति समिति का अध्यक्ष पदेन **RBI** गवर्नर होते हैं। छह सदस्यीय इस समीति तीन सदस्य **RBI** से और 3 सदस्य बाहर से होते हैं।
- हाल ही में **RBI** के गवर्नर ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से करों में कटौती की सिफारिश की है।
- हाल ही में संपन्न हुई मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, जिसमें कहा गया है कि सरकारों को पेट्रोल और डीजल लगने वाले अप्रत्यक्ष कर **(Indirect Taxes)** में कटौती करनी चाहिए।

- पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है जबकि राज्य सरकारें वैट लगाती हैं।
- इस समय पेट्रोल और डीजल के बेसिक मूल्य में तो बहुत वृद्धि नहीं हुई है लेकिन टैक्स में वृद्धि के कारण पेट्रोल की कीमतें कई राज्यों में 100 रूपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार गई हैं।
- **RBI** गवर्नर ने कहा है कि पेट्रोल-डीजल मूल्य में वृद्धि से अन्य उत्पादों का मूल्य बढ़ेगा जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी। इस मंहगाई दर लगभग 5.5-6 प्रतिशत के बीच में है जो उच्चतम है। इससे अधिक होने पर अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- भारत चीन और अमेरिका के बाद कच्चे तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 211.6 मिलियन टन तेल का उपभोग करता हैं इस उपभोग में से मात्र 35 मिलियन टन का उत्पादन ही भारत के अंदर होता है। इस तरह भारत अपनी आवश्यकता का 84-89 प्रतिशत तेल आयात करता है।
- हमारे यहां कच्चे तेल को आयात करके उसे भंडारित करने की क्षमता बहुत कम है, जिसके कारण हम कच्चे तेल को कम कीमत पर खरीदकर बड़ी मात्रा में स्टोर नहीं कर पाते हैं। इससे जब भी कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि होती है, हमारे यहां भी तेल का मूल्य बढ़ जाता है, हालांकि मूल्य बढ़ने का यह सबसे प्रमुख और इकलौता कारक नहीं है।

- पेट्रोल की कीमत 4 कारकों पर निर्भर है। यह कारक- **Base Price, State Tax, Central Tax** और **Delaer Commission** है।
- बेस प्राइस कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य होता है। कच्चे तेल का प्रति बैरल (159 लीटर) मूल्य डॉलर में तय होता है। प्रति बैरल मूल्य बढ़ने पर भारतीय कंपनियों को भी अधिक मूल्य पर तेल खरीदना पड़ता है। मई 2014 में कच्चे तेल की कीमतें 106.85 डॉलर प्रति बैरल थी। आज अमेरिकी **WTI** क्रूड ऑयल 61 डॉलर प्रति बैरल और लंदन क्रूड लगभग 65 डॉलर प्रति बैरल के आस पास है।
- इस तरह कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अनुसार हमारे यहां तेल का मूल्य कम होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा ही है।
- इस मूल्य वृद्धि का एक प्रमुख कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है। मई 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10.38 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4.52 रुपये प्रति लीटर था। इसमें अब तक 13 बार वृद्धि हो चुका है। इस समय पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.83 रुपये प्रति लीटर लग रहा है।
- बेस प्राइस- पेट्रोल और डीजल का मूल्य

पेट्रोल		डीजल	
अप्रैल	फरवरी	अप्रैल	फरवरी

	2014	2021	2014	2021
बेस प्राइस	47.13	32.10	44.45	33.71
केंद्र का टैक्स	10.38	32.90	4.52	31.80
डीलर कमीशन	2.00	3.68	1.19	2.51
राज्य का टैक्स	11.90	20.61	6.55	11.68
कुल कीमत	71.41	89.29	56.71	79.70

	क्रूड ऑयल की कीमत डॉलर में	पेट्रोल की कीमत रुपये में	डीजल की कीमत रुपये में
मई 2015	106.85	71.41	56.71
मई 2016	63.82	63.16	49.57
मई 2017	45.01	62.19	50.95
मई 2018	50.57	68.09	57.35
मई 2019	75.25	74.63	65.93
मई 2020	70.01	73.13	66.71
मई 2021	30.61	69.59	62.29
फरवरी 2021	65.19	90.93	81.32

- केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों द्वारा वैट (VAT) लगाना जाता है, जो हर राज्य अपने हिसाब से लगाता है। राजस्थान में वैट की दर पेट्रोल पर 38 प्रतिशत और डीजल पर 28 प्रतिशत है। मणिपुर,

कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में 33-35 प्रतिशत बैट पेट्रोल पर लग रहा है।

- एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई 68 प्रतिशत बढ़ी

आंकड़े करोड़ में-

वर्ष	रुपये
2013-14	77,982
2014-15	99,068
2015-16	178,477
2016-17	242,691
2017-18	229,716
2018-19	214,369
2019-20	2,23,057
2020-21	1,31,545

(2020-21 के आंकड़े पहली छमाही के)

- पेट्रोल-डीजल पर वैट/सेल्स टैक्स से राज्य सरकारों की कमाई

आंकड़े करोड़ में-

वर्ष	रुपये
2013-14	1,29,045
2014-15	1,37,157
2015-16	1,42,807

2016-17	1,66,414
2017-18	1,85,850
2018-19	2,01,265
2019-20	2,00,493
2020-21	78,168

(2020-21 के आंकड़े पहली छमाही के)

- पड़ेसी देशों में सिर्फ बांग्लादेश में पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ी, वो भी मामूली

	पेट्रोल		डीजल	
	अप्रैल 2014	फरवरी 2021	अप्रैल 2014	फरवरी 2021
भारत	72.26	90.58	55.49	80.97
पाकिस्तान	66.17	51.13	71.27	53.04
बांग्लादेश	74.43	76.40	52.55	55.80
श्रीलंका	74.92	60.26	56.17	38.92
नेपाल	83.61	68.97	65.84	58.31